



आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
**Ministry of Housing
and Urban Affairs**
Government of India

साप्ताहिक सूचना पत्र



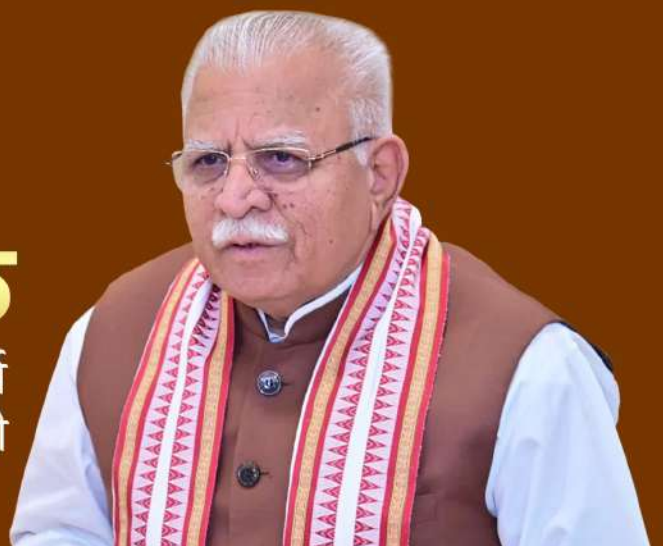
दिनांक 2.10.2026 से 8.10.2026

5 वाँ संस्करण



श्री मनोहर लाल

माननीय केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य
तथा विद्युत मंत्री





**Ministry of Housing
and Urban Affairs**
Government of India

सप्ताह की प्रमुख उपलब्धियाँ

- 1 9 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी से 'स्वच्छता ही सेवा 2026' को मिली गति
- 2 'सबके लिए पर्याप्त आवास' विषय के साथ विश्व पर्यावास दिवस 2026 का आयोजन
- 3 DMRC अकादमी में मोज़ाम्बिक के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत आधुनिक तकनीकों का किया अवलोकन
- 4 PMAY-U 2.0 की डिजिटल पहल: मोबाइल ऐप और पुनर्निर्मित वेबसाइटें लॉन्च
- 5 सर्कुलर इकोनॉमी आधारित शहरी विकास को गति देने के लिए CIIIS 2.0 की समीक्षा
- 6 HUDCO के FY 2026-27 के प्रदर्शन लक्ष्यों पर MoHUA के साथ समझौता

साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

2 अक्टूबर, 2026

9 करोड़ से अधिक लोगों की भागीदारी से 'स्वच्छता ही सेवा 2026' को मिली गति

Overall Citizens Participation: 9,21,08,264 National Campaign Roll-out Households Participated: 2,46,32,899				
Transformation of Cleanliness Target Units (CTUs) and Clean Public Places	Swachh Paathshala -Yuva for Swachhata	SafaiMitra Suraksha Evam Samman Shivirs	Advocacy Total Participants 63,47,115	
15,02,821 Total CTUs	4,88,897 Awareness Activities Conducted	82,804 Shivirs Conducted	22,59,036 4-Way Waste Segregation	15,44,645 Swachh Bazaar
14,26,221 CTUs Transformed	1,09,822 RRR Drives Conducted	3,08,214 Sanitation Workers Participated	76,177 Neki Ki Deewar/ RRR Centers	2,86,391 Swachh Mohalla (Events)
5,42,87,875 Total Participants	35,16,620 School Children Participated	1,11,661 Preventive Health Checkup Camps Organised	9,38,827 Clean Green Festivities	1,45,827 Swachh Offices (Events)
3,17,574 Public Places Cleaned	80,651 Swachhata Gyan Yatra organised	3,63,812 PPE Kits Distributed	9,26,343 Sports for Swachhata	6,78,264 Clean Water Bodies
1,90,02,829 People Engaged	11,80,740 Swachhata Gyan YatraParticipation	12,69,395 Scheme Beneficiaries	3,07,085 Home, Community and RWA Composting	



17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2026 अभियान 'स्वच्छता में सहभाग; स्वच्छ भारत, विकसित भारत' थीम के तहत स्वच्छता के लिए स्वेच्छिक भागीदारी और सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दे रहा है। अब तक 9 करोड़ से अधिक लोग इस अभियान में भाग ले चुके हैं। इसके तहत 14 लाख से अधिक Cleanliness Target Units (CTUs) का कार्याकल्प किया गया है, 3 लाख से अधिक सार्वजनिक स्थलों की सफाई की गई है और 11 लाख से अधिक लोगों ने सफाई कर्मचारियों के लिए आयोजित हेल्थ कैंप में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, SWM Rules 2026 पर 4 लाख से अधिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई हैं, जिनमें 35 लाख से अधिक स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं।

2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस और गांधी जयंती के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने नई दिल्ली स्थित संकल्प भवन में आयोजित 'स्वच्छ रंगोली' पहल में भाग लिया। इस पहल के माध्यम से जिम्मेदार विकल्प अपनाने, व्यक्तिगत भागीदारी और स्वच्छ एवं अधिक सतत पर्यावरण के महत्व को रेखांकित किया गया।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

गांधी जयंती पर केंद्रीय मंत्री श्री जे.पी. नड्डा ने नई दिल्ली में कर्तव्य भवन-1 के निकट आयोजित स्वच्छता श्रमदान में भाग लिया। इस अवसर पर माननीय राज्य मंत्री (PP) डॉ. जितेंद्र सिंह, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) की सचिव श्रीमती निवेदिता शुक्ला वर्मा तथा विभागीय अधिकारी भी उपस्थित रहे। गोवा में केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने अभियान में भाग लेते हुए समर्पित सेवाओं के लिए स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नानकमत्ता साहिब में स्वच्छता अभियान का नेतृत्व किया, जबकि दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज़ादपुर में श्रमदान किया।

राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों ने भी कई पहलें आयोजित कीं। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नागरिकों को कचरा संग्रहण वाहनों को ट्रैक करने और कचरे से भरे इस्टबिन की सूचना देने में सहायता के लिए 'कचरा गाड़ी' ऐप लॉन्च किया गया। विजयवाड़ा में 'स्वच्छथॉन 2026' का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें 22 राज्यों के 10,000 से अधिक फिटनेस प्रेमियों ने भाग लिया। पणजी में Reduce, Reuse, Recycle (RRR) अभियान के तहत एक ही दिन में 300 किलोग्राम से अधिक कपड़े, टेक्सटाइल, किताबें, खिलौने और जूते एकत्र किए गए।



झारखंड में सभी 49 Urban Local Bodies (ULBs) में 'सफाईमित्र सुरक्षा एवं सम्मान शिविर' आयोजित किए गए, जिनका मुख्य उद्देश्य सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर ध्यान देना था। इस पहल के तहत 8,289 से अधिक सफाईमित्रों को सम्मानित किया गया, 7,830 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, 685 आयुष्मान कार्ड बनवाने में सहायता प्रदान की गई, 2,367 PPE किट वितरित किए गए, 877 NAMASTE ID Cards जारी किए गए और 4,038 लोगों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहायता की गई वहीं, मणिपुर में आयोजित 11 किलोमीटर की 'Run for Clean Manipur' दौड़ में युवाओं, राज्य के अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। इस पहल ने स्वच्छ एवं विकसित भारत के निर्माण में सामूहिक भागीदारी के महत्व को और मजबूत किया।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

5 अक्टूबर, 2026

सबके लिए पर्याप्त आवास' विषय के साथ विश्व पर्यावास दिवस 2026 का आयोजन



आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा विश्व पर्यावास दिवस 2026 का आयोजन किया गया। इस वर्ष का विषय 'सबके लिए पर्याप्त आवास' था। कार्यक्रम में नवाचार, नीतिगत सुधारों, प्रौद्योगिकी और सतत वित्तपोषण के माध्यम से शहरी आवास व्यवस्था को सुदृढ़ करने पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर मंत्रालय के सचिव श्री सतेंद्र सिंह; राजधानी विकास विभाग की सचिव श्रीमती डी. थोरा; संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, सबके लिए आवास प्रभाग, श्री कुमार रविकांत सिंह; UN-Habitat के प्रतिनिधि; मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी; राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रधान सचिव तथा अन्य हितधारक शामिल हुए। HUDCO, NHB और NIUA सहित विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। इस समारोह ने सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, समावेशी और गरिमापूर्ण आवास सुनिश्चित करने की दिशा में भारत के निरंतर प्रयासों को रेखांकित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 (PMAY-U 2.0) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य हितधारकों के योगदान को भी मान्यता दी गई।

कार्यक्रम के दौरान HUDCO, NCHF, NHB, CGEWHO, NIUA और BMTPC के विभिन्न प्रकाशनों का विमोचन किया गया। इसके अतिरिक्त, NHB, HUDCO और BMTPC द्वारा विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए आयोजित चित्रकला प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। इन प्रतियोगिताओं में दिव्यांग बच्चे भी शामिल थे।

कार्यक्रम में शहरी आवास से जुड़ी प्रमुख चुनौतियों और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा के लिए तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इनमें किराये के आवास, आवास की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने, नियामक ढांचे तथा किफायती आवास क्षेत्र में नवीन निमाण प्रौद्योगिकियों और वित्तपोषण की भूमिका जैसे विषय शामिल रहे।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

8 अक्टूबर, 2026

DMRC अकादमी में मोज़ाम्बिक के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत, आधुनिक तकनीकों का किया अवलोकन



मोज़ाम्बिक सरकार के परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स मंत्री श्री जोआओ जॉर्ज माटलोम्बे ने 8 अक्टूबर 2026 को DMRC अकादमी का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल का स्वागत DMRC के प्रबंध निदेशक डॉ. विकास कुमार तथा DMIL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय जामुआर ने किया। इस दौरान उन्हें DMRC एवं DMIL द्वारा संचालित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण संबंधी पहलों की जानकारी दी गई।

दौरे के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने DMRC एवं DMIL पर आधारित डॉक्यूमेंट्री देखी और अकादमी की अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का अवलोकन किया। इनमें एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) लेब, मेट्रो सिग्नलिंग मॉडल रूम, बोगी ब्रेक्स न्यूमैटिक सिमुलेटर तथा RS-2 ड्राइविंग सिमुलेटर शामिल हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन स्थित दिल्ली मेट्रो संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां उसे दिल्ली मेट्रो की विकास यात्रा और उपलब्धियों से अवगत कराया गया।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

5 अक्टूबर, 2026

PMAY-U 2.0 की डिजिटल पहल: मोबाइल ऐप और पुनर्निर्मित वेबसाइटें लॉन्च



प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 के मोबाइल एप्लिकेशन का विमोचन किया गया। यह पहल डिजिटल माध्यम से जानकारी तक पहुंच को सुदृढ़ करने और योजना से संबंधित सेवाओं को अधिक सुलभ, पारदर्शी तथा लाभार्थी-केंद्रित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

इस मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से नागरिक PMAY-U 2.0 के तहत सीधे आवेदन कर सकते हैं और योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी एवं सेवाओं तक समयबद्ध पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। इससे लाभार्थियों को योजना के विभिन्न पहलुओं की जानकारी आसानी से उपलब्ध होगी और उनके समग्र अनुभव में सुधार आएगा। यह एप्लिकेशन Android और iOS, दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जिससे अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ उठा सकेंगे।

कार्यक्रम के दौरान PMAY-U और PMAY-U 2.0 की पुनर्निर्मित वेबसाइटों का भी विमोचन किया गया। इन वेबसाइटों को DBIM 3.0 और GIGW 3.0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप तैयार किया गया है। इनके माध्यम से दोनों योजनाओं से संबंधित आवश्यक जानकारी एक सुलभ, उपयोगकर्ता-अनुकूल और एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई है। यह पहल आवास योजनाओं से जुड़ी डिजिटल सेवाओं तक नागरिकों की पहुंच को बेहतर बनाने में सहायक होगी।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

6 अक्टूबर, 2026

सर्कुलर इकोनॉमी आधारित शहरी विकास को गति देने के लिए CIIIS 2.0 की समीक्षा

CIIIS कार्यक्रम आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA), French Development Agency (AFD), German Development Bank (KfW), European Union और National Institute of Urban Affairs (NIUA) की संयुक्त पहल है। इसके दूसरे चरण CIIIS 2.0 के तहत Circular Economy के सिद्धांतों पर आधारित 18 सतत अवसंरचना परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन परियोजनाओं का मुख्य फोकस Integrated Solid Waste Management है। इसके अतिरिक्त, कार्यक्रम के माध्यम से राज्यों में जलवायु परिवर्तन से संबंधित पहलों को भी समर्थन प्रदान किया जा रहा है।

5 से 7 अक्टूबर 2026 तक AFD टीम और CIIIS PMU ने CIIIS 2.0 के Maturation Phase की निगरानी के तहत मुजफ्फरपुर, बिहार में संयुक्त Field Mission आयोजित किया। इस दौरान परियोजनाओं की प्रगति, क्रियान्वयन संबंधी प्राथमिकताओं, प्रस्तावित हस्तक्षेपों और नियोजित व्यय की समीक्षा की गई।

टीम ने बिहार के State Mission Director, श्री अनिमेष कुमार पराशर, IAS से मुलाकात कर परियोजनाओं से जुड़े प्रमुख घटनाक्रमों पर चर्चा की। इसके बाद Muzaffarpur Smart City के CEO, श्री ऋतुराज प्रताप, IAS के साथ बैठक में क्रियान्वयन की प्रगति और विभिन्न गतिविधियों में तेजी लाने के उपायों की समीक्षा की गई।

मिशन के दौरान AFD, CIIIS PMU और शहर के हितधारकों के बीच समन्वय पर भी चर्चा हुई। साथ ही, मुजफ्फरपुर के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेपों, क्रियान्वयन की रणनीति और नियोजित व्यय की समीक्षा की गई। यह संयुक्त मिशन CIIIS 2.0 के तहत परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।



साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

1 अक्टूबर, 2026

HUDCO के FY 2026-27 के प्रदर्शन लक्ष्यों पर MoHUA के साथ समझौता



Housing and Urban Development Corporation Limited (HUDCO) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) के शहरी विकास विभाग के साथ वार्षिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस MoU में वित्त वर्ष के लिए HUDCO के प्रमुख प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

MoU पर MoHUA के शहरी विकास विभाग के सचिव श्री सतेंद्र सिंह और HUDCO के CMD श्री संजय कुलश्रेष्ठ ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर MoHUA और HUDCO के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। हस्ताक्षर समारोह में MoHUA के संयुक्त सचिव श्री कुमार रविकांत सिंह और श्री संजीत (JSFA), HUDCO के श्री एम. नागराज (DCP) तथा श्री दलजीत सिंह खत्री (DF) भी शामिल हुए।

MoU में वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रदर्शन से जुड़े व्यापक मानक शामिल हैं। इनमें प्रमुख वित्तीय अनुपात, Total Return to Shareholders (TRS), Micro and Small Enterprises (MSEs) से खरीद, Corporate Social Responsibility (CSR) पर व्यय तथा अन्य प्रदर्शन संकेतक शामिल हैं।

प्रदर्शन लक्ष्यों को वित्त मंत्रालय के Department of Public Enterprises (DPE) द्वारा समन्वित अंतर-मंत्रालयी प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप दिया गया है। यह MoU वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान HUDCO के रणनीतिक और परिचालन उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

2.10.2026 से 8.10.2026



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

राष्ट्रीय सागर (8 अक्टूबर, 2026)

यूपी में 950 पिक टॉयलेट तैयार, 275 नए ब्लॉक्स पर काम जारी

लखनऊ : प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के लिए सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन-नगरीय के तहत अब तक नगरीय निकायों में करीब 950 पिक टॉयलेट बनाए जा चुके हैं। वहीं, 189 नगरीय निकायों में 275 नए पिक टॉयलेट ब्लॉक्स के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। इन ब्लॉक्स में कुल 1,100 सीटें होंगी। नगर विकास विभाग के अनुसार, नए पिक टॉयलेट बाजारों, प्रमुख मार्गों, सार्वजनिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में महिलाओं की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर अलग, सुरक्षित और सुविधाजनक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराना है।

नवोदय टाइम्स (7 अक्टूबर, 2026)

शहरी गरीबों के लिए पी.एम. आवास योजना: पंजाब को 1.05 लाख, हरियाणा को 74,658 घर मिले

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पी.एम.ए.वाई.-यू) के तहत गरीबों को घर दिलाने में यूपी और महाराष्ट्र 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ऊपर हैं। अधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 13 जुलाई, 2026 तक 99.07 लाख घर बनकर तैयार हो गए और सही लोगों को दे दिए गए। इनमें यूपी 17.25 लाख और महाराष्ट्र 10.74 लाख घरों के साथ दूसरे नंबर पर था। ये घर शहरी इलाकों के गरीबों को दिए गए।

दिलचस्प बात यह है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक महाराष्ट्र की शहरी आबादी 5.08 करोड़ होने के बावजूद, यूपी की 4.44 करोड़ की तुलना में महाराष्ट्र का हिस्सा कम था, ऐसा आधिकारिक सूत्र का कहना है।

डाटा के विश्लेषण से यह भी पता चल रहा है कि अर्बन हाउसिंग स्कीम के तहत फायदा पाने वाले राज्यों में गुजरात देश में तीसरे नंबर पर है, जहां 9.93 लाख घर बने हैं, जबकि इसकी शहरी आबादी 2.57 करोड़ है, जबकि तमिलनाडु की आबादी 3.49 करोड़ है। तमिलनाडु को सिर्फ 6.32 लाख घर मिले।

सरकार ने 127.68 लाख घर बनाने और देने के लिए 2.12 लाख करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इनमें से 121.03 लाख घर 13 जुलाई, 2026 तक लक्ष्यपूर्वियों को सौंप दिए गए हैं। सरकार ने हाउसिंग स्कीम के लिए अब तक 1.81 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं। टारगेट 31 मार्च, 2027 तक शहरी इलाकों में रहने वाले सभी योग्य लोगों के लिए घर पूरे करना है। मध्य प्रदेश 9.10 लाख यूनिट के साथ चौथे नंबर पर था, जबकि पश्चिम बंगाल का हिस्सा 5.38 लाख यूनिट और ओडिशा का 1.74 लाख यूनिट था। अगर पंजाब को 1.05 लाख घर मिले, तो हरियाणा में शहरी गरीबों को 74,658 घर मिले।

ऑफ रिकॉर्ड

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: डीडीए के पाकों, हरित क्षेत्रों और खेल परिसरों में चल रहे महीनेभर के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के दौरान करीब 2.5 टन कचरा एकत्र किया है। यह अभियान 17 सितंबर से एलजी तरनजीत सिंह संघू के नेतृत्व में शुरू हुआ है। अभियान के तहत डीडीए ने 'ग्रीन से जुड़ें बच्चे-सीखें, देखभाल करें और भाग लें', 'कूड़ेदान भरने से पहले' और 'राजधानी का संकल्प' नाम से तीन विशेष पहल शुरू की हैं। इसके तहत साकेत, नेताजी सुभाष, हरिनगर, पश्चिम विहार, द्वारका सेक्टर-11 व 17, मेजर ध्यानचंद, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, चिल्ला, यमुना खेल परिसर समेत कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग संग्रह के लिए हरे और नीले रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। इनके भरने से पहले ही अब कूड़ा उठाया जाएगा।

हिंदुस्तान (8 अक्टूबर, 2026)

अनधिकृत कॉलोनीयों में जीआईएस सर्वे जल्द होगा

तैयारी

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनीयों में रहने वाले लोगों को संबंधित अधिकार दिलाने के लिए अब सभी 13 जिलों में जीआईएस सर्वे और मैपिंग होगी।

पीएम-उदय योजना को पारदर्शी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली में 'फुट' (दिल्ली रेवेन्यू ऐंड इमॉनस सर्वे, सेक्टरल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट) योजना के तहत आधुनिक जीआईएस सर्वे और मैपिंग प्रणाली विकसित करने के लिए 65 करोड़ रुपये की परियोजना को स्वीकृति दी है। इसका तहत दिल्ली के सभी 13 जिलों में पीएम-उदय और मुख्यमंत्री राहत स्कीम को लागू है।

मुख्यमंत्री राहत स्कीम का पहला है कि इस परियोजना में 80 फीसदी वाले 52 करोड़ रुपये आवंटन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की शहरी विकास निधि (यूडीए) से अनुदान के रूप में मिलेगी, जबकि बाकी 20 फीसदी राज्य 13 करोड़ की एकमिलियन सरकार का राजस्व विभाग देगा। इस परियोजना को राजस्व विभाग से लागू करेगा। 'फुट' परियोजना के माध्यम से

65 करोड़ रुपये की 'फुट' परियोजना को मंजूरी
पीएम-उदय योजना को रफ़्तार मिलने की उम्मीद

पीएम-उदय योजना के लिए नियोजित और जीआईएस अनिवार्य सर्वे कराया जाएगा। सेक्टरल के माध्यम से अनधिकृत कॉलोनीयों और पावनों की संख्याओं का निश्चित किया जाएगा। इन कॉलोनीयों में सभी निर्माण का प्रचार दर्ज किया जाएगा। इससे संबंधित सभी और दस्तावेजी प्रक्रिया को जल्द व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा सकेगा।

मुख्यमंत्री राहत स्कीम को लागू है कि इस परियोजना में 80 फीसदी वाले 52 करोड़ रुपये आवंटन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की शहरी विकास निधि (यूडीए) से अनुदान के रूप में मिलेगी, जबकि बाकी 20 फीसदी राज्य 13 करोड़ की एकमिलियन सरकार का राजस्व विभाग देगा। इस परियोजना को राजस्व विभाग से लागू करेगा। 'फुट' परियोजना के माध्यम से

दैनिक जागरण (5 अक्टूबर, 2026)

डीएमआरसी के एमडी को 'आज का कर्मवीर' पुरस्कार

नई दिल्ली, वि.: दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन के एमडी डा. विकास कुमार को ब्यूरोक्रेटिक एक्सीलेंस श्रेणी में प्रतिष्ठित 'आज का कर्मवीर' पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुंबई में आयोजित समारोह में महाराष्ट्र के कौशल विकास एवं नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने विकास कुमार को सम्मान प्रदान किया।



दैनिक जागरण (5 अक्टूबर, 2026)

डीडीए के खेल परिसरों से निकला 2.5 टन कचरा, अब कूड़ेदान भरने से पहले होगा उठान

राज्य ब्यूरो, जागरण • नई दिल्ली: डीडीए के पाकों, हरित क्षेत्रों और खेल परिसरों में चल रहे महीनेभर के 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान के दौरान करीब 2.5 टन कचरा एकत्र किया है। यह अभियान 17 सितंबर से एलजी तरनजीत सिंह संघू के नेतृत्व में शुरू हुआ है। अभियान के तहत डीडीए ने 'ग्रीन से जुड़ें बच्चे-सीखें, देखभाल करें और भाग लें', 'कूड़ेदान भरने से पहले' और 'राजधानी का संकल्प' नाम से तीन विशेष पहल शुरू की हैं। इसके तहत साकेत, नेताजी सुभाष, हरिनगर, पश्चिम विहार, द्वारका सेक्टर-11 व 17, मेजर ध्यानचंद, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, चिल्ला, यमुना खेल परिसर समेत कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग संग्रह के लिए हरे और नीले रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। इनके भरने से पहले ही अब कूड़ा उठाया जाएगा।

शुरू की हैं। इसके तहत साकेत, नेताजी सुभाष, हरिनगर, पश्चिम विहार, द्वारका सेक्टर-11 व 17, मेजर ध्यानचंद, पूर्वी दिल्ली खेल परिसर, चिल्ला, यमुना खेल परिसर समेत कई स्थानों पर सफाई अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान गीले और सूखे कचरे के अलग-अलग संग्रह के लिए हरे और नीले रंग के कूड़ेदान लगाए गए हैं। इनके भरने से पहले ही अब कूड़ा उठाया जाएगा।



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

दैनिक जागरण

(7 अक्टूबर, 2026)

सुपरटेक परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 9620 करोड़ के टेंडर

नई दिल्ली, प्रेडः सरकारी कंपनी एनबीसीसी ने सुपरटेक लिमिटेड की 16 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 9,620 करोड़ के टेंडर जारी किए हैं। इन परियोजनाओं में वर्षों से हजारों घर खरीदार फंसे हुए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नेशनल ब्रिलिडिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनबीसीसी) के अनुसार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और कर्नाटक में फैली इन 16 परियोजनाओं में करीब 50,000 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। कंपनी ने निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए कुल 25 टेंडर जारी किए हैं, जिनकी अनुमानित राशि 9,620.33 करोड़ रुपये है। कंपनी ने कहा कि परियोजनाओं को फिर से शुरू करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है और इससे लंबे समय से अपने घरों का इंतजार कर रहे खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

द पायनियर

(7 अक्टूबर, 2026)

पीएनबी हाउसिंग फाइनांस ने शुरू की पीएमएवाई यात्रा

■ 6 राज्यों के 30 से अधिक शहरों में बढ़ाएगी
किफायती आवास की जागरूकता

पायनियर समाचार सेवा। मेरठ

पीएनबी हाउसिंग फाइनांस ने प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0) के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने और किफायती आवास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीएमएवाई यात्रा अभियान की शुरुआत की है। मेरठ से शुरू हुआ यह अभियान उत्तर प्रदेश सहित गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु के 30 से अधिक शहरों तक पहुंचाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य पीएमएवाई-यू 2.0 से जुड़ी जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना तथा पात्र परिवारों को योजना के लाभ समझाने के साथ उन्हें आवास वित्त से जोड़ना है। इसके तहत कैटर वैन, नुककड़ नाटक, जादू के प्रदर्शन, जागरूकता केंद्र, हेल्पडेस्क और वाहनों पर ब्रांडिंग जैसी गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लोगों से सीधे संपर्क किया जाएगा। अभियान की शुरुआत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस के चीफ बिजनेस ऑफिसर-रिटेल मुकेश अग्रवाल और चीफ बिजनेस ऑफिसर-अफोर्डेबल बिजनेस सतीश कुमार सिंह ने वरिष्ठ नेतृत्व टीम



के साथ की। कंपनी के एमडी एवं सीओ अजय शुक्ला ने कहा कि पीएमएवाई-यू 2.0 ने घर खरीदने की इच्छा रखने वाले परिवारों के लिए नए अवसर उपलब्ध कराए हैं, लेकिन योजना की जानकारी वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाना अभी भी महत्वपूर्ण चुनौती है। पीएमएवाई यात्रा के माध्यम से कंपनी लोगों तक जानकारी, मार्गदर्शन और सहायता पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मुकेश अग्रवाल ने कहा कि देश के उभरते शहरों में घर खरीदने की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोगों को उपलब्ध आवास योजनाओं की जानकारी देने वाले संपर्क केंद्रों की आवश्यकता है। वहीं, सतीश कुमार सिंह ने कहा कि पीएमएवाई-यू 2.0 के माध्यम से किफायती आवास पर सरकार का फोकस औपचारिक आवास वित्त की पहुंच बढ़ाने में मदद कर रहा है। पीएनबी हाउसिंग फाइनांस ने हाल ही में कानपुर और सिलीगुड़ी में पीएमएवाई नोडल शाखाएं शुरू की हैं।

स्वतंत्र भारत

(6 अक्टूबर, 2026)

विश्व पर्यावास दिवस पर उत्तर प्रदेश को मिले 02 प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार

स्वतंत्र भारत व्यूरो, लखनऊ। विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर सोमवार को आवासन एवं शहरी कार्य

-पीएम आवास
योजना-शहरी में देश
भर में लहाराया परचम

मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अन्तर्गत शानदार उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश को 02 महत्वपूर्ण श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। जो पुरस्कार मिले हैं उनमें प्रथम पुरस्कार (सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन) योजना के

लाभार्थी आधारित आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने के लिए उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में 'प्रथम स्थान' प्राप्त हुआ। तृतीय पुरस्कार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में स्वीकृत आवासों को कुल संख्या के सापेक्ष सर्वाधिक प्रतिशत आवासों की ग्राइडिंग (धरातल पर कार्य शुरू करने) के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को तृतीय स्थान से पुरस्कृत किया गया।

यह दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के यह दोनों प्रतिष्ठित पुरस्कार केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के

माननीय राज्य मंत्री लेखन साहू द्वारा प्रदान किए गए। इस गरिमामयी अवसर पर केन्द्र सरकार के शहरी विकास विभाग के सचिव सतेन्द्र सिंह एवं श्रीमती डी तारा तथा संयुक्त सचिव, कुमार रमिकांत सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से यह पुरस्कार राज्य नगरीय विकास अधिकरण (सूड) के निदेशक मोहन बहदुर सिंह ने ग्रहण किया। पुरस्कार वितरण समारोह में उत्तर प्रदेश प्रतिनिधित्व मण्डल का नेतृत्व कर रहे निदेशक, सूड के साथ वित्त नियन्त्रक राजनीकान्त वर्मा और कार्यक्रम अधिकारी अतुल सिंह चौहान भी मौजूद रहे। राज्य की इस बढ़ती सफलता पर निदेशक, सूड द्वारा विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं प्रेषित की।



Ministry of Housing and Urban Affairs Government of India

सत्यमेव जयते

इस सप्ताह के प्रमुख समाचार

राजस्थान पत्रिका

(6 अक्टूबर, 2026)

विश्व पर्यावास दिवस: दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ को पुरस्कार पीएम आवास योजना में छत्तीसगढ़ की 'बेस्ट प्रैक्टिस' को राष्ट्रीय पहचान

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

रायपुर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती एवं सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे नवाचारी और प्रभावी कार्यप्रणाली को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। ईडब्ल्यूएस-एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण तथा एएचपी के माध्यम से आवास उपलब्ध कराने की उत्कृष्ट कार्यप्रणाली के लिए भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया है। विश्व पर्यावास दिवस के अवसर पर सोमवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने छत्तीसगढ़



दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय राज्यमंत्री पुरस्कार प्राप्त करते।

को यह पुरस्कार प्रदान किया। राज्य की ओर से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा तथा राज्य शहरी विकास अभिकरण के

25413 आवासों के लिए बिना खर्च जमीन

राज्य सरकार ने निजी कॉलोनीयों में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी वर्ग के लिए भूमि आरक्षण के प्रावधान को प्रभावी ढंग से लागू किया है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में 25 हजार 413 आवासों के निर्माण के लिए बिना सरकारी खर्च के भूमि उपलब्ध हुई है। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 के अंतर्गत 17 हजार 790 और प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत 7 हजार 623 आवास शामिल हैं।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी-सह-राज्य मिशन संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सुमित अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया।

दैनिक भास्कर

(5 अक्टूबर, 2026)

'स्वच्छता ही सेवा' अभियान, पाकों से 2.5 टन कचरा जुटाया

भास्कर न्यूज़ | नई दिल्ली

दिल्ली को स्वच्छ और हरा-भरा बनाने के लिए उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधु के मार्गदर्शन में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का एक महीने का 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान जारी है। 17 सितंबर से शुरू हुए अभियान के तहत डीडीए के पाकों, ग्रीन स्पेस और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सफाई और पौधारोपण गतिविधियां की जा रही हैं। करीब 75 आरडब्ल्यूए, स्कूली छात्र, बच्चे और स्थानीय नागरिक इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 'कैप्टिवल्स प्रॉमिस' अभियान में पाकों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई व रखरखाव पर ध्यान दिया जा रहा है। डीडीए के अनुसार साकेत, द्वारका, यमुना, हरिनगर, विल्ला और कुतुब गॉल्फ कोर्स समेत प्रमुख स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 2.5 टन कचरा एकत्र किया गया। डीडीए ने लोगों से कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने की अपील की है।

दैनिक जागरण

(4 अक्टूबर, 2026)

आइआइटी दिल्ली व अन्य संस्थानों के छात्रों ने ली नमो ट्रेन की जानकारी



नमो ट्रेन के बारे में जानकारी लेते आइआइटी दिल्ली के छात्र। लो. एक्सप्रेस अटॉर्नेस

नई दिल्ली: नरेन्द्र मोदी सरकार के 12 वर्षों में हुए बदलाव के उपलक्ष्य में भारत सरकार की रिफॉर्म डेस्क पहल के तहत नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण, संस्थागत सुधारों और जनकल्याण को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालयों और विभागों द्वारा किए गए प्रमुख परिवर्तनकारी उपायों से जनता को परिचित कराया जा रहा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने सराय काले छां नमो भारत स्टेशन पर आइआइटी दिल्ली और अन्य संस्थानों के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। उन्हें इसके माध्यम से नमो भारत ट्रेन के बारे में जानकारी दी गई।

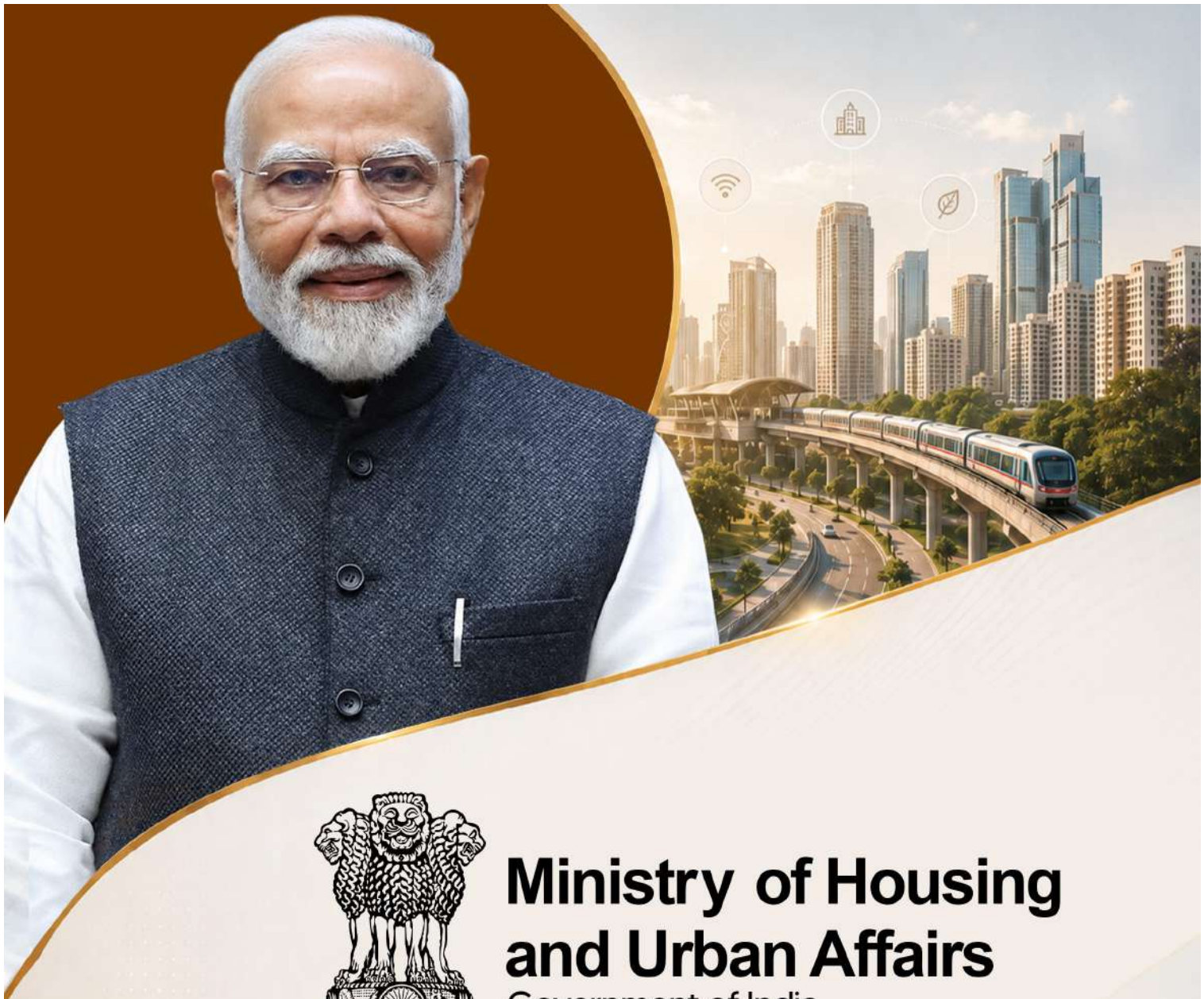
अमर उजाला

(5 अक्टूबर, 2026)

एनसीआरटीसी को मिला आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के लिए राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर 2026 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कंक्रिट इंजीनियर्स एसोसिएशन (सीईए) की ओर से आयोजित सीईए एनुअल रिकग्निशन अवॉर्ड्स 2026 में दिया गया। यह पुरस्कार दिल्ली-मेरठ नमो भारत परियोजना में बेहतर इंजीनियरिंग, सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को अपनाने के लिए एनसीआरटीसी को दिया गया है। साथ ही, परियोजना को तय समय और बजट के भीतर पूरा करने के प्रयासों को भी सम्मानित किया गया। एनसीआरटीसी के अनुसार, यह पुरस्कार आधुनिक परिवहन ढांचे के विकास और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में दिल्ली-मेरठ नमो भारत आरआरटीएस परियोजना के योगदान को भी रेखांकित करता है।





सत्यमेव जयते

Ministry of Housing and Urban Affairs

Government of India



**Office of
Manohar Lal**

Hon'ble Union Minister of Housing & Urban Affairs and Power

